

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 666
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है।

फेम इंडिया के चरण-II की शुरुआत

666. श्री आर. वैद्यलिंगम:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि भारत में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाया जाना एवं विनिर्माण किया जाना (फेम) के पायलट चरण या चरण 1 की शुरुआत सरकार द्वारा 2015 में की गई थी, जो 31 मार्च, 2018 को समाप्त हो गई;
- (ख) क्या सरकार 'फेम इंडिया' के चरण-II की शुरुआत करने का विचार कर रही है;
- (ग) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक (विद्युत) ट्रेन पर आधार मल्टीमॉडल परिवहन के शुरुआत की घोषणा की है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क) और (ख): हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इसकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से दो वर्षों की आरंभिक अवधि (चरण-I) के लिए नामतः फेम इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण] योजना तैयार की। फेम इंडिया योजना की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के चरण-I में प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर उचित रूप से स्कीम की समीक्षा की जाएगी। तथापि, फेम इंडिया योजना का चरण-I, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से शुरू होकर आरंभ में दो वर्षों की अवधि के लिए था, को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया गया है।

भारी उद्योग विभाग को इस योजना के लिए अगले कदमों की तैयारी करनी है।

(ग) और (घ): सार्वजनिक परिवहन में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के तहत इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन पर आधारित सार्वजनिक और साझा मोबिलिटी के लिए मांग प्रोत्साहनों को बढ़ाने हेतु दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों और विशेष श्रेणी के राज्यों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को एक रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई। इस प्रतिक्रिया में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार से ₹4054.60 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता लेते हुए 3144

ई-बसों, 2430 ई-फोर व्हीलर टेक्सियों और 21545 ई- थ्री व्हीलर ऑटो की कुल आवश्यकता के साथ 21 राज्यों के 44 शहरों से 47 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों की जांच करने के बाद चयन मानदंड के आधार पर निधियन हेतु निम्नलिखित ग्यारह (11) शहरों का चयन किया गया:-

क्रम संख्या	शहर	बस	चौपहिया	तिपहिया
1.	दिल्ली	40	-	-
2.	अहमदाबाद	40	20	20
3.	बेंगलुरु	40	100	500
4.	जयपुर	40	-	-
5.	मुंबई	40	-	-
6.	लखनऊ	40	-	-
7.	हैदराबाद	40	-	-
8.	इंदौर	40	50	200
9.	कोलकाता	40	200	-
विशेष श्रेणी के राज्यों के शहर				
10.	जम्मू	15	-	-
11.	गुवाहाटी	15	-	-
	कुल	390	370	720

चुने गए शहरों को निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देना और दिनांक 28 फरवरी, 2018 से पहले आपूर्ति आदेश जारी करना अपेक्षित है। इस रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से भारी उद्योग विभाग द्वारा फेम इंडिया योजना (चरण-I) के तहत लगभग ₹437 क58/5रोड़ खर्च किए जाने की संभावना है, जिसमें चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु प्रोत्साहनों के रूप में लगभग ₹40 करोड़ शामिल हैं।
